वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नीति–विषयक दस्तावेज के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना भारत सरकार की कार्यसूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए, कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन, उत्पादकता तथा लाभप्रदता में वृद्धि करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थल–विशिष्ट, किफायती तथा जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने के लिए तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों की सहभागिता आधारित अनुसंधान की दिशा में अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कुलपति की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समितियाँ गठित की हैं। अन्य सभी कुलपति तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक, सम्बद्ध क्षेत्र के निदेशक, अटारी, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से प्रत्येक से एक नामिती एवं संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। राज्य–विशिष्ट दस्तावेज विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान, इन रणनीतियों पर चर्चा करने तथा इनमें संशोधन करने के लिए परिषद के स्तर पर कई समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। जिनमें प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, प्रोफेसर रमेश चंद, संबंधित विभागों के सचिवों तथा गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य हितधारकों सहित प्रख्यात विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया ताकि इन रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए विशेषज्ञों के व्यापक और विषद अनुभव का लाभ उठाया जा सके। इन दस्तावेजों में राज्यों की सभी कृषि पारिस्थितिकियों के लिए रणनीतियां शामिल की गई हैं और ऐसा करते समय बागवानीए पशुधन, मात्स्यिकी, कृषि वानिकी तथा सस्योपरान्त प्रसंस्करण क्रियाओं के विकास के लिए राज्यों में विद्यमान संभावनाओं और क्षमताओं को ध्यान में रखा गया है। इन दस्तावेजों में उक्त प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाने के लिए रणनीतियां उपलब्ध करवाने के साथ–साथ में उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी, गुणवत्ता में सुधार आदि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

संबंधित राज्यों की सभी कृषि पारिस्थितिकियों में कार्यान्वयन हेतु राज्यवार तैयार इन दस्तावेजों को माननीय कृषि मंत्री जी तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्तर पर राज्य सरकारों को उपलब्ध करवाया गया है। राज्य स्तरीय समन्वय समितियां इन रणनीतियों को कार्यान्वित करने एवं आवश्यक तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इनके कार्यान्वयन की निगरानी में संलग्न हैं। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान राज्यों को इन रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए सलाह दे रही है तथा गैर सरकारी संगठनों एवं राज्य एजेंसियों सहित अन्य हितधारकों को इस कार्य से जोड़ कर कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से कुछ चयनित गांवों में कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों नें किसानों की आय को दोगुना करने हेतु महत्वपूर्ण पहल की हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी के मॉडल के तहत डीसीएस श्रीराम लिमिटेड (डीएसएल) नई दिल्ली के साथ मिलकर किसानों की आय को दोगुना करने हेतु गन्ना क्षेत्र की क्षमता का दोहन करते हुए दो जिलों के आठ गांवों में सभी 2028 किसान परिवारों की आय को दोगुना करने के लिए चार चीनी मिलों के कमान क्षेत्र में संयुक्त उद्यम शुरू किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थानों में भी ऐसे ही मॉडल विकसित और प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।

वर्तमान संस्करण एक सार दस्तावेज है जो विस्तृत राज्य–विशिष्ट दस्तावेजों से विकसित किया गया है तथा इसमें विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किए जाने हेतु दृष्टिकोण, प्रमुख रणनीतियां तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग और कुछ मामलों में कुछ चयनित प्रकरण अध्ययन (केस स्टडीज)/सफलता गाथाएं भी संक्षेप में शामिल की गई हैं। इस दस्तावेज में निर्दिष्ट रणनीतियों में एक ही समय पर कई कार्य निष्पादित करते हुए कृषि कार्य को कृषि–उद्यम में बदलने की दृष्टि से कृषि–व्यवसाय पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने तथा मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करने से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से इतर (नॉन फार्म) रोजगार के अवसरों का सृजन करने में सहायता मिलेगी। हमें पूर्ण आशा है कि नीति निर्माताओं, किसानों, फील्ड में कार्यरत विस्तार कार्मिकों और संबंधित वैज्ञानिकों के अतिरिक्त विभिन्न विकास एजेंसियां एवं विभाग इस दस्तावेज को उपयोगी पाएंगे और यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सपने को साकार करने में सार्थक भूमिका निभाने में सक्षम होगा।